



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४०]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च १७, १९७१/फाल्गुन २६, १८९२

No. 40]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1971/PHALGUNA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Kandla Free Trade Zone Committee)

RESOLUTION

New Delhi, the 15th March 1971

No. 3/3/70-FTZ.—The working of the two committees functioning at present for Kandla Free Trade Zone viz, Kandla Free Trade Zone Selection Committee and Kandla Free Trade Zone Screening Committee has been reviewed by the Government and it has been decided to merge these two committees into a single high powered committee to be called "KANDLA FREE TRADE ZONE COMMITTEE" to ensure expeditious decisions on the cases relating to Kandla Free Trade Zone.

2. The terms and reference of the Kandla Free Trade Zone Committee herein-after called the 'COMMITTEE' will be as under:—

- (i) Consideration of the applications and approving proposals for setting up industries in the Free Trade Zone at Kandla. In cases where an Industrial Licence is necessary under the rules in force, the committee will only make recommendations for final approval of the case by the Licensing Committee set up under the Industries (D&R) Act, 1951 in the Department of Industrial Development.

- (ii) Taking decisions on rate of raw materials import content or replenishment in lieu of a normal AU entitlement plus import entitlement against exports under REP in cases where it is felt that normal AU entitlements may not be quite adequate for purposes of 100 per cent export. For units in the Zone where import of raw materials is to be freely permitted there would be one replenishment rate and not separate entitlements under AU/REP, the degree of replenishment being decided by the Committee.
- (iii) Taking decisions on the imported raw materials requirements of the units in the zone for their first months export production.
- (iv) Taking decisions on the rate of export assistance to be granted independently of the normal assistance admissible to other exporters in India, in cases where it is felt that the rate of export assistance should be fixed on a basis other than the normal rate of assistance.
- (v) Taking decisions on fixation of limits and disposal of sub-standard goods and wastages of various units in the zone.
- (vi) Taking decisions on Capital Goods requirements of the entrepreneurs in the KFTZ within the powers delegated to this committee by the main C. G. Committee from time to time. At present, the C. G. Committee has delegated powers to the committee to clear cases involving import of Capital Goods up to the value of Rs. 7.5 lakhs only; and
- (vii) Taking decisions on the terms and conditions of foreign collaboration involving non-resident investments in the zone within such powers as may be delegated to the committee by the Foreign Investment Board from time to time.

(At present no powers are delegated but it would be open to the FIB to consider limited and well defined delegation of powers in the same manner as the C. G. Committee)

3. The composition of the committee will be as under:—

Chairman

1. Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Foreign Trade, New Delhi.

Members

2. Economic Adviser to the Government of India.
3. Joint Secretary, Ministry of Foreign Trade.
4. Director (Export Assistance), Ministry of Foreign Trade.
5. Director (FT&T Division), Ministry of Finance, Department of Expenditure.
6. Chairman, Kandla Port Trust, Gandhidham.
7. Collector of Customs, Bombay as representative of Department of Revenue & Insurance.
8. Senior Industrial Adviser (Engg.), D.G.T.D.
9. Senior Industrial Adviser (Chemicals), D.G.T.D.
10. Chief Auditor, Department of Economic Affairs.
11. Deputy Secretary (Licensing Policy & Industrial Coordination), Department of Industrial Development.
12. Joint Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.
13. Industries Commissioner, Department of Industries, Government of Gujarat Ahmedabad.
14. Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham.

Member-Secretary

15. Officer on Special Duty (FTZ), Ministry of Foreign Trade, New Delhi.

4. The Committee is authorised to co-opt any other officer of the Government of India in order to assist in its deliberations and to appoint sub-committee as and when required.

5. The headquarter of the Committee will be in the main Secretariat of the Ministry of Foreign Trade. The Committee may, however, meet at any place in India. The Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Ministry of Foreign Trade.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

V. S. MISHRA, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र समिति

संकल्प

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1971

सं० 3/3/70-एफ०टी०जेड :—कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये इस समय कार्य कर रही दो समितियों अर्थात् कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रवरण समिति तथा कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र जांच समिति के कार्य चलन की सरकार द्वारा समीक्षा की गई और यह विनिश्चित किया गया है कि इन दोनों समितियों के “कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र समिति” नामक एकाकी उच्चाधिकार समिति में विलय कर दिया जाये, ताकि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर शीघ्रतापूर्वक विनिश्चय करना सुनिश्चित हो सके।

2. कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र समिति, जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘समिति’ कहा जाएगा, के विचारार्थ विषय निम्नोक्त होंगे :—

- (1) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदनों पर विचार करना तथा प्रस्तावों को स्वीकार करना। जिन मामलों में लागू नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है, समिति, औद्योगिक विकास विभाग में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्थापित लाइसेंस समिति द्वारा मामले की अन्तिम स्वीकृति के लिये केवल सिफारिशें करेगी।
- (2) ऐसे मामलों में जहां यह अनुभव किया जाता है कि शतप्रतिशत निर्यात के प्रयोजनों के लिए सामान्य वास्तविक प्रयोक्ता हकदारियां समुचित रूप से पर्याप्त नहीं हैं, रजिस्टर्ड निर्यातकों सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत निर्यातों के बदले सामान्य वास्तविक प्रयोक्ता हकदारी तथा आयात हकदारी के स्थान पर कच्चे माल के आयात अंश अथवा प्रतिपूर्ति की दर के सम्बन्ध में विनिश्चय करना। क्षेत्र में उन एककों के लिए जहां कच्चे माल के आयात की मुक्त रूप से अनुमति है वहां प्रतिपूर्ति की दर एक होगी और वास्तविक प्रयोक्ता/रजिस्टर्ड आयातकों सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत अलग अलग हकदारियां नहीं होगी, प्रतिपूर्ति का निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।
- (3) क्षेत्र में एककों की, उनकी पहले 6 महीने के लिये निर्यात उत्पादन के सम्बन्ध में, आयातित कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं का विनिश्चय करना।

- (4) ऐसे मामलों में जहां यह समझा जाये कि निर्यात सहायता की दर सहायता की सामान्य दर से इतर किसी अन्य आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, भारत में अन्य निर्यातकों को देय सामान्य सहायता पर विचार किये बिना दी जाने वाली निर्यात सहायता की दर के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ।
- (5) क्षेत्र में विभिन्न एककों के अद्योमानक सामान तथा व्यर्थ माल की सीमाओं को निर्धारित करने तथा उसे निपटाने के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ।
- (6) समय समय पर मुख्य पूंजीगत माल समिति द्वारा इस समिति को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्यमकर्तृओं की पूंजीगत माल सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में विनिश्चय करना । इस समय पूंजीगत माल समिति ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए समिति को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जिसमें 7.5 लाख रु० मूल्य तक के ही पूंजीगत माल के आयात से सम्बन्धित मामले शामिल हैं; और
- (7) विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा समिति को समय समय पर दी जाने वाली शक्तियों के अन्तर्गत, क्षेत्र में, ऐसे विदेशी सहयोग की शर्तों के सम्बन्ध में विनिश्चय करना, जिसमें अनिवासी पूंजी अंतर्गस्त हो ।

(इस समय कोई शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं परन्तु विदेशी निवेश बोर्ड को पूंजीगत माल समिति के समान सीमित तथा सुस्पष्ट रूप में शक्तियों के प्रत्यायोजन पर विचार करने का अधिकार होगा) ।

3. समिति का गठन निम्नाक्त प्रकार होगा :—

- (1) अपर सचिव, भारत सरकार, विदेशी व्यापार मंत्रालय, नई दिल्ली—अध्यक्ष
- (2) आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार सदस्य
- (3) संयुक्त सचिव, विदेशी व्यापार मंत्रालय ,,
- (4) निदेशक (निर्यात सहायता), विदेशी व्यापार मंत्रालय ,,
- (5) निदेशक (एफ टी० एण्ड टी० डिबीजन) वित्त मंत्रालय का व्यव. विभाग ,,
- (6) अध्यक्ष, कांडला पत्तन ट्रस्ट, गांधीधाम ,,
- (7) राजस्व तथा बीमा विभाग के प्रतिनिधियों के रूप में सीमा शुल्क समाहर्ता, ,,
बम्बई ।
- (8) वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरिंग), तकनीकी विकास महा- ,,
निदेशालय ।
- (9) वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (रसायन), तकनीकी विकास ,,
महा-निदेशालय ।
- (10) मुख्य लेखा-परीक्षक, आर्थिक कार्य विभाग ,,
- (11) उप सचिव (लाइसेंस नीति तथा औद्योगिक समन्वय) औद्योगिक विकास ,,
विभाग ।
- (12) आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, नई दिल्ली ,,
- (13) उद्योग आयुक्त, उद्योग विभाग, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ,,

- (14) विकासायुक्त, काङ्गला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम सदस्य
- (15) विशेष कार्य अधिकारी (मुक्त व्यापार क्षेत्र)
विदेशी व्यापार मंत्रालय, नई दिल्ली । सदस्य सचिव

4. समिति को उसके कार्य में सहायता के लिए भारत सरकार के किसी अन्य अधिकारी को सहयोजित करने, तथा यदि और जब आवश्यक हो, उप-समितियां नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

5. समिति का मुख्यालय विदेशी व्यापार मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में होगा । परन्तु समिति की बैठक भारत में किसी स्थान पर भी हो सकती है । समिति को अमला सम्बन्धी सहायता विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा दी जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० एस० मिश्रा, संयुक्त सचिव ।

